हसीना की यात्रा से मैत्री को मिले नए आयाम

बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता शेख मुजीब-उर-रहमान की बेटी शेख हसीना के साथ भारत का रिश्ता 1971 से है। शेख मुजीब को पाकिस्तानी जेल में कैद करके रखा गया था और रिहाई युद्ध समाप्ति के बाद हुई, जब 16 दिसंबर, 1971 के दिन पाकिस्तानी फौज ने भारतीय सेना और 'मुक्ति-बाहिनी' के सामने हथियार डाले थे। लेकिन बाद में शेख हसीना के लिए जिंदगी उथल-पुथल भरी रही।

जी पार्थसारथी

लेखक पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं।

हाल ही में अपने पड़ोसी मुल्कों के सबसे सम्माननीय नेताओं में एक और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का स्वागत आधिकारिक तौर पर भारत आने पर किया गया। बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता शेख मुजीब-उर-रहमान की बेटी शेख हसीना के साथ भारत का रिश्ता 1971 से है। शेख मुजीब को पाकिस्तानी जेल में कैद करके रखा गया था और रिहाई युद्ध समाप्ति के बाद हुई, जब 16 दिसंबर, 1971 के दिन पाकिस्तानी फौज ने भारतीय सेना और 'मुक्ति-बाहिनी' के सामने हथियार डाले थे। लेकिन बाद में शेख हसीना के लिए जिंदगी उथल-पुथल भरी रही। उनके पिता शेख मुजीब, माता फैज़लतुन्निसा मुजीब और तीन भाइयों को 15 अगस्त, 1975 के दिन ढाका के राष्ट्रपति निवास में विद्रोही सैनिकों ने कत्ल कर दिया। उस नृशंस तख्तापलट के वक्त शेख हसीना और उनकी बहन जर्मनी में थीं, इसलिए बची रहीं। सालों तक मुजीब-उर-रहमान की हत्या के पीछे विदेशी हाथ होने की खबरें आती रहीं। लेकिन तमाम विपरीत हालातों के बावजूद शेख हसीना ने बांग्लादेश में वापसी की और पिता की अवामी लीग पार्टी में फिर से जान फूंकी। वर्ष 1996 में वे पहली मर्तबा प्रधानमंत्री चुनी गईं और 2001 तक सरकार चलाई। शेख हसीना उस वक्त पार्टी अध्यक्ष थीं, जब उन्होंने 2009 में चुनाव जीतने के बाद पुनः प्रधानमंत्री का ओहदा संभाला। शेख हसीना की बांग्लादेश में धार्मिक सौहार्द्र कायम रखने के लिए प्रतिबद्धता अविचलित रही है। हालांकि पाकिस्तान वहां के कट्टरपंथियों को मदद देता रहा है। पिछले सालों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संबंध बिगड़े हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तान-परस्त कट्टरपंथियों से सख्ती से निपटा जा रहा है।

जहां पाकिस्तान की कोशिश रही कि दक्षेस एक बेमानी संगठन बनकर रह जाए, वहीं भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान को साथ लिए बिना, क्षेत्रीय सहयोग सुनिश्चित करने में लगे हैं। इस हेतु बिम्सटेक नामक संगठन के माध्यम से, जिसके सदस्यों में थाइलैंड, म्यांमार, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के अलावा बंगाल की खाड़ी के तमाम राष्ट्र हैं, प्रभावशाली ढंग से काम जारी है। भारत ने पाक के अलावा बाकी दक्षेस राष्ट्रों के साथ मुक्त-व्यापार संबंध जारी रखा है। अभी हमारे पूरबी पड़ोसियों के साथ नौवहनीय सहयोग पर अधिक ध्यान केंद्रित करना बाकी है। जब 1971 में बांग्लादेश बना तो अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसींजर ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय भिखारी बनने जा रहा है, जिसे सदा विदेशी

खैरात की जरूरत पड़ेगी। हालांकि बांग्लादेश ने एक सतत आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर दिखाई, पाकिस्तान की बनिस्बत, जो अपने आर्थिक वजूद के लिए हमेशा सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, चीन से लेकर यूरोपियन यूनियन के मुल्कों के अतिरिक्त विश्व बैंक की मदद पर निर्भर है। वहीं बांग्लादेश ने काबिले तारीफ आर्थिक वृद्धि हासिल की है, जो 2012 में 6 फीसदी से बढ़कर 2018 में 8.15 प्रतिशत हो गई। जाहिर है कोविड के चलते वृद्धि दर 2021 में सिकुड़कर 3.51 प्रतिशत रही। हालांकि एशियाई विकास बैंक ने इस साल बांग्लादेश के लिए अनुमान 6 फीसदी लगाया है। लेकिन बांग्लादेश ने वस्त्र उद्योग में कमाल किया, जिसका वार्षिक उत्पादन 34 बिलियन डॉलर जा पहुंचा है, यह बांग्लादेश के कुल निर्यात का 80 प्रतिशत हिस्सा है। आज बांग्लादेश दुनियाभर में वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।

शेख हसीना वर्ष 2009 से चौथी बार प्रधानमंत्री के ओहदे पर हैं। उन्हें विपक्षी बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी और कट्टर इस्लामिक गुटों जैसे कि जमात-ए-इस्लामी के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी अर्से से वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सांप्रदायिक सौहार्द्र पर पहले की भांति अडिग हैं। दक्षेस और बिमस्टेक सहित अनेक सहयोग संगठनों में अनेकानेक मुद्दों पर वे भारत की तगड़ी भागीदार रही हैं। 1975 में अपने पिता और अन्य पारिवारिक सदस्यों की निर्मम हत्या की गंभीर जांच के लिए उन्होंने निर्णायक रुख कायम रखा। विगत में अमेरिका के साथ शेख हसीना के रिश्ते असहज रहे हैं, जो दर्शाता है कि अमेरिकी अभी भी पुराने पूर्वाग्रह ढो रहे हैं।

भारत ने बांग्लादेश के साथ अपने आर्थिक सहयोग को लगातार विस्तार दिया है, विशेषकर सड़क और रेल संपर्क क्षेत्र में। पिछले साल भारत ने बांग्लादेश को 98 लाख कोविड वैक्सीन टीके भेजे थे। पिछले दशक में, भारत ने बांग्लादेश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास के लिए 8 बिलियन मूल्य की तीन बड़ी योजनाओं के लिए ऋण दिया है। इनमें संचार, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधा शामिल हैं। सबसे मुश्किल संधि वार्ता गंगाजल बंटवारे के लिए फरक्का समझौते को लेकर रही। रोचक है कि 1977 में इस संधि के लिए भारत की ओर से अगुवाई तत्कालीन रक्षा मंत्री जगजीवन राम ने की थी, जिन्हें पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे का पूरा समर्थन और सहयोग हासिल था। जाहिर है कि भारत-बांग्लादेश के बीच संबंध पश्चिम बंगाल के लोगों की भावनाओं और चिंताओं को नज़रअंदाज करके नहीं बन सकते, खासकर नदियों के पानी पर। ऐसे में जरूरी है कि विगत की तरह, भारत सरकार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ निकट एवं निरंतर सलाह बनाकर तीस्ता नदी के पानी बंटवारे पर समझौता वार्ताओं में तेजी लाए।

बांग्लादेश को म्यांमार से आए लगभग 9,19,000 रोहिंग्या शरणार्थियों का बोझ अकेले सहना पड़ रहा है क्योंकि भारत ने और ज्यादा रोहिंग्याओं को शरण देने से मना कर दिया है। यह समय है कि भारत म्यांमार के साथ बात करते ऐसा माहौल बनवाए कि रोहिंग्याओं की अपने घरों में वापसी हो सके। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त और अन्य संयुक्त राष्ट्र संगठनों को भी शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित बनाने को सकारात्मक योगदान करना चाहिए। भू-राजनैतिक लिहाज से, म्यांमार में भारतीय तट के नजदीक चीन के सहयोग से बनाए जा रहे क्याक्पयू बंदरगाह पर नजदीकी नज़र रखनी चाहिए। यह चीन निर्मित बंदरगाह म्यांमार में भारत द्वारा विकसित किए गए सित्त्वे बंदरगाह से भी काफी निकट है, जिसका मंतव्य म्यांमार से होकर हमारे उत्तर-पूरबी राज्यों के वास्ते समुद्र तक पहुंच मार्ग बनाना है। जहां क्वाड संगठन का संयुक्त हित मलक्का की खाड़ी के पश्चिम में बढ़ती चीनी उपस्थिति पर नज़र बनाए रखना है वहीं भारत के लिए पूरबी सागरीय क्षेत्र में इंडोनेशिया के साथ सहयोग बढ़ाना महत्वपूर्ण रहेगा।

लेखक पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं।